PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD, LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 026
दि. 26.10.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

डिजिटल बैंकिंग को मिलेगी नई सुरक्षा, भुवनेश्वर में आरबीआई के डेटा सेंटर का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा को दी बड़ी सौगात, करीब 169 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान; डिजिटल लेनदेन, भुगतान प्रणालियों और वित्तीय आंकड़ों की सुरक्षा को मिलेगी मजबूती

भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। करीब 169 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह अत्याधुनिक सुविधा देश की डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, मजबूत और भरोसेमंद बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग का दायरा लगातार बढ़ने के बीच इस केंद्र से वित्तीय आंकड़ों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के संचालन और साइबर सुरक्षा से जुड़ी क्षमताओं को मजबूती देने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने समावेशी विकास पर जोर देते हुए कहा कि विकास का लाभ गांवों, छोटे शहरों और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

ओडिशा में स्थापित यह केंद्र केवल एक तकनीकी परिसर नहीं, बल्कि तेजी से बदलती वित्तीय व्यवस्था की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। देश में डिजिटल लेनदेन के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंकिंग सेवाओं को आम लोगों के लिए पहले की तुलना में अधिक सुलभ बनाया है। मोबाइल फोन के माध्यम से धन हस्तांतरण, ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल बैंकिंग और विभिन्न वित्तीय सेवाओं का उपयोग अब छोटे कारोबारियों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों तक फैल रहा है। इसके साथ ही वित्तीय प्रणालियों पर साइबर हमलों, आंकड़ों की चोरी और तकनीकी व्यवधानों से बचाव की आवश्यकता भी बढ़ी है। ऐसे में आरबीआई के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना को वित्तीय व्यवस्था की तकनीकी तैयारी मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

यह केंद्र ओडिशा के जटनी क्षेत्र स्थित इन्फो वैली-II में 18.55 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है। इसकी आधारशिला 22 मार्च 2023 को तत्कालीन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रखी थी। परियोजना के तहत डेटा सेंटर के साथ साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण तकनीकी सेवाओं के संचालन को समर्थन देना और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करना है। डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार के साथ बैंकिंग व्यवस्था को लगातार उपलब्ध बनाए रखना, संवेदनशील आंकड़ों की सुरक्षा करना और तकनीकी जोखिमों से निपटने की क्षमता बढ़ाना जरूरी हो गया है। यह सुविधा इन जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की गई है।

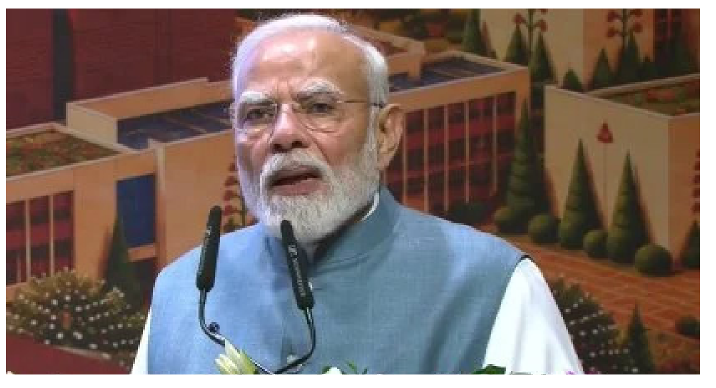

आज बैंकिंग व्यवस्था का बड़ा हिस्सा डिजिटल तकनीक पर निर्भर है। ग्राहकों के खातों से जुड़ी जानकारी, भुगतान संबंधी रिकॉर्ड और विभिन्न वित्तीय सेवाओं का सुचारु संचालन सुरक्षित तकनीकी प्रणालियों पर आधारित होता है। यदि इन प्रणालियों में कोई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी आती है या साइबर हमले के कारण सेवाएं प्रभावित होती हैं, तो इसका असर केवल किसी एक बैंक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बड़ी संख्या में ग्राहकों और कारोबारियों को परेशानी हो सकती है। इसलिए वित्तीय क्षेत्र में डेटा सेंटर जैसी सुविधाओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। इनका उद्देश्य आंकड़ों के प्रबंधन और तकनीकी सेवाओं के संचालन को व्यवस्थित समर्थन देना तथा वित्तीय प्रणालियों की विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद करना है।

साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान इस परियोजना का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तकनीक के विस्तार के साथ साइबर अपराधों के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। धोखाधड़ी वाले संदेश, फर्जी वेबसाइट, संदिग्ध लिंक, पहचान संबंधी जानकारी की चोरी और ऑनलाइन भुगतान में हेरफेर जैसी चुनौतियां वित्तीय संस्थानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। इनसे निपटने के लिए केवल आधुनिक तकनीकी उपकरण पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि प्रशिक्षित विशेषज्ञों, जागरूक कर्मचारियों और समय के साथ विकसित होती सुरक्षा प्रक्रियाओं की भी आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से साइबर सुरक्षा से संबंधित ज्ञान और कौशल विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों को उभरते जोखिमों को समझने और उनसे निपटने की तैयारी करने का अवसर मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान डिजिटल बैंकिंग से आम लोगों को मिल रहे लाभों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग ने लोगों को चौबीसों घंटे बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ग्राहकों को धन हस्तांतरण, भुगतान और अनेक बैंकिंग कार्यों के लिए हर बार बैंक की शाखा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मोबाइल और इंटरनेट आधारित सेवाओं के कारण समय की बचत होती है और वित्तीय लेनदेन अधिक सुविधाजनक बनते हैं। इस बदलाव का लाभ केवल बड़े शहरों में रहने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल बढ़ा है।

प्रधानमंत्री ने विकास को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए छोटे कारोबारियों, पारंपरिक कारीगरों, रेहड़ी-पटरी वालों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का उल्लेख किया। डिजिटल भुगतान की सुविधा ने इन वर्गों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने के नए अवसर दिए हैं। छोटे दुकानदार अब ग्राहकों से डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार कर सकते हैं, जबकि ग्राहकों को नकदी रखने की निर्भरता कम करने का विकल्प मिलता है। पारंपरिक कारीगरों और छोटे उद्यमियों के लिए भी डिजिटल लेनदेन कारोबार को व्यवस्थित करने तथा भुगतान प्राप्त करने का सुविधाजनक माध्यम बन सकता है। हालांकि, इन सुविधाओं का पूरा लाभ तभी संभव है, जब लोगों को डिजिटल सेवाओं के सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी हो और उन्हें भरोसेमंद बैंकिंग ढांचा उपलब्ध कराया जाए।

डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के साथ वित्तीय समावेशन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है। वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिल सके। लंबे समय तक ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कई बार कठिन रहा है। डिजिटल तकनीक ने इस दूरी को कम करने में मदद की है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता और साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। ऐसे में तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ आम लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री का गांवों और छोटे शहरों तक विकास का लाभ पहुंचाने पर जोर इसी व्यापक आवश्यकता से जुड़ा है। आरबीआई का नया केंद्र ऐसे समय में स्थापित किया गया है, जब देश की भुगतान प्रणालियों में तकनीकी बदलाव तेजी से हो रहे हैं। डिजिटल भुगतान की बढ़ती मात्रा के कारण वित्तीय लेनदेन की गति, विश्वसनीयता और सुरक्षा को बनाए रखना आवश्यक हो गया है। भुगतान एवं निपटान प्रणालियां अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को सुचारु बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। इन प्रणालियों में व्यवधान आने से आम ग्राहकों, व्यापारियों और संस्थानों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। इसलिए इनसे जुड़ी तकनीकी सेवाओं को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए मजबूत व्यवस्था की जरूरत है। नया डेटा सेंटर इस दिशा में आवश्यक तकनीकी समर्थन देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। वित्तीय आंकड़ों की सुरक्षा भी इस परियोजना के महत्व का प्रमुख पहलू है। बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी मात्रा में संवेदनशील जानकारी का इस्तेमाल होता है। ग्राहकों की पहचान, खातों से संबंधित विवरण और भुगतान रिकॉर्ड जैसी जानकारियों की सुरक्षा बनाए रखना वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की डेटा चोरी या साइबर सेंधमारी से ग्राहकों के भरोसे को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा, डिजिटल सेवाओं में लगातार उपलब्धता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए वित्तीय क्षेत्र में सुरक्षित डेटा प्रबंधन, तकनीकी निगरानी और साइबर सुरक्षा की तैयारी को मजबूत करना महत्वपूर्ण माना जाता है। ओडिशा के जटनी स्थित इन्फो वैली-II में इस सुविधा का निर्माण राज्य के तकनीकी बुनियादी ढांचे के लिए भी महत्वपूर्ण है। 18.55 एकड़ में विकसित परिसर में डेटा सेंटर और प्रशिक्षण संस्थान का एक साथ होना वित्तीय तकनीक तथा साइबर सुरक्षा से जुड़े कार्यों को संस्थागत आधार प्रदान करता है। हालांकि, किसी भी ऐसी परियोजना का वास्तविक प्रभाव उसके प्रभावी संचालन, सुरक्षा मानकों के पालन, विशेषज्ञ मानव संसाधन और समय के साथ तकनीकी उन्नयन पर निर्भर करता है। तेजी से बदलते साइबर खतरों के बीच इन व्यवस्थाओं को लगातार अद्यतन रखना जरूरी होगा।

सुनवाई का मौका दिए बिना वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा नाम: भूपेंद्र यादव

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना मतदाता सूची से उसका नाम नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत ही पूरी की जानी चाहिए। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की जिम्मेदारी है कि किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को जवाब देने और अपनी बात रखने का उचित अवसर दिया जाए। यादव ने एसआईआर को निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए इसका बचाव किया और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया और कानून के अनुरूप संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची की जांच करना और उसमें दर्ज विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करना है। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि मतदाता का नाम हटाना कोई मनमानी कार्रवाई नहीं हो सकती। संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में मतदाता सूची में नाम हटाए जाने को लेकर उठने वाली शिकायतों का निपटारा नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। यादव ने एसआईआर के इतिहास का उल्लेख करते हुए दावा किया कि वर्ष 1950 से अब तक देश में आठ बार विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और मौजूदा प्रक्रिया नौवीं है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि एसआईआर कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी एक पुरानी प्रणाली है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, आठवीं बार यह प्रक्रिया कांग्रेस के शासनकाल में पूरी हुई थी। उन्होंने इस तथ्य का हवाला देते हुए विपक्ष के उन सवालों पर आपत्ति जताई, जिनमें मौजूदा पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। देश में मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। चुनाव में मतदान का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए मतदाता का नाम संबंधित मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। इसलिए सूची में सही नामों का शामिल रहना और अपात्र या गलत प्रविष्टियों की पहचान करना निर्वाचन व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं। वहीं, इस प्रक्रिया के दौरान किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हट जाने की आशंका भी गंभीर विषय है। इसी कारण मतदाता सूची में संशोधन और नाम हटाने की कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन तथा संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना महत्वपूर्ण माना जाता है।

एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और नाम हटाए जाने की आशंकाओं पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना रहा है कि पुनरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर न हो और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। इन चिंताओं के जवाब में भूपेंद्र यादव ने कहा कि किसी मतदाता का नाम मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि नाम हटाने से पहले संबंधित मतदाता को जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि चुनावी परिणामों के बाद वह संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। हालांकि, एसआईआर को लेकर जारी बहस केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध मतदाता सूची की विश्वसनीयता, नागरिकों के मतदान अधिकार और निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों के भरोसे से है। ऐसे में पुनरीक्षण के दौरान नियमों का पालन, शिकायतों का समयबद्ध निपटारा और मतदाताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण रहेगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने या उसमें संशोधन की प्रक्रिया को लेकर नागरिकों के बीच जागरूकता भी आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को अपने नाम, पते या अन्य विवरण में गड़बड़ी दिखाई देती है, तो उसे निर्वाचन आयोग की निर्धारित व्यवस्था के तहत इसकी जानकारी देनी चाहिए। इसी तरह, यदि किसी मतदाता को नाम हटाए जाने संबंधी सूचना मिलती है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। निर्वाचन अधिकारियों के लिए भी जरूरी है कि वे संबंधित मामलों की जांच करते समय लागू नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें। भूपेंद्र यादव के बयान का मुख्य संदेश यही रहा कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्रवाई नियमों के अनुरूप होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना उसका नाम नहीं हटाया जा सकता।

जजों की नियुक्ति में सरकार के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम थे चंद्रचूड़ : पूर्व जज कौल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस तेज होने के संकेत हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान कॉलेजियम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अपनी आगामी पुस्तक विदाउट फियर ऑर फेवर में कौल ने आरोप लगाया है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में चंद्रचूड़ सरकार के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम रुख अपना रहे थे। कौल के मुताबिक, नियुक्तियों से जुड़े कुछ फैसलों में सरकार की राय पहले से जानने पर विचार किया गया, जबकि उनके अनुसार ऐसे मामलों पर निर्णय कॉलेजियम की औपचारिक बैठक में चर्चा के बाद होना चाहिए था। उन्होंने आशंका जताई कि यदि नियुक्तियों से पहले सरकार की सहमति लेने की प्रवृत्ति सामान्य बन गई, तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कॉलेजियम की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।

कौल ने अपनी पुस्तक में एक ऐसी घटना का उल्लेख किया है, जो उनके और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के बीच नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर मतभेदों को सामने लाती है। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के छह रिक्त पदों को भरने के लिए कॉलेजियम की बैठक होनी थी और पांच नामों पर सहमति बन चुकी थी। इसी दौरान छठे नाम का प्रस्ताव सामने आया। कौल का दावा है कि चंद्रचूड़ ने इस नाम पर सरकार की राय जानने के लिए फोन करने पर विचार किया था। कौल ने इस तरीके पर अपनी असहमति जताई और कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े सभी नामों पर कॉलेजियम की औपचारिक बैठक में विचार किया जाना चाहिए।

पूर्व न्यायाधीश के मुताबिक, इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान चंद्रचूड़ ने उन्हें अलग कमरे में बुलाकर सरकार से राय लेने की बात कही थी। कौल को आशंका थी कि कुछ नामों को लेकर सरकार की सहमति पहले ही प्राप्त की जा चुकी हो सकती है और छठे नाम के मामले में भी ऐसा करने पर विचार हो रहा था। उन्होंने अपनी पुस्तक में सरकार से परामर्श करने और नियुक्ति से पहले उसकी मंजूरी लेने के बीच अंतर को महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार, सरकार की राय जानना एक बात है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले उसकी सहमति को आवश्यक मान लेना अलग बात है। कौल का तर्क है कि इस अंतर को नजरअंदाज करने से कॉलेजियम की निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय न्यायिक व्यवस्था का संवेदनशील विषय है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था के तहत वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह नामों पर विचार करता है और सिफारिशें करता है। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना और नियुक्तियों में कार्यपालिका के सीधे नियंत्रण को सीमित करना है। नियुक्तियों की प्रक्रिया में सरकार की भूमिका और कॉलेजियम की स्वायत्तता को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। कौल ने अपनी पुस्तक में इसी व्यापक सवाल को उठाते हुए कहा है कि यदि कॉलेजियम औपचारिक चर्चा से पहले सरकार की सहमति लेने लगे, तो भविष्य में यह एक स्थापित परंपरा का रूप ले सकता है।

कौल ने चेतावनी दी कि इस तरह की प्रक्रिया को सामान्य मान लिया गया, तो आने वाले मुख्य न्यायाधीशों पर भी सरकार से पहले सहमति लेने का दबाव बन सकता है। उनके अनुसार, यह स्थिति विशेष रूप से उन मुख्य न्यायाधीशों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिनका कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटा होता है। यदि नियुक्तियों से संबंधित निर्णयों में अनौपचारिक सहमति को प्राथमिकता मिलने लगे, तो कॉलेजियम की औपचारिक बैठकों और सामूहिक विचार-विमर्श की भूमिका कमजोर पड़ने की आशंका पैदा हो सकती है। कौल का मानना है कि न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को स्पष्ट, संस्थागत और स्वतंत्र बनाए रखना जरूरी है, ताकि किसी भी निर्णय को लेकर भविष्य में गलत परंपरा स्थापित न हो।

पूर्व न्यायाधीश ने कॉलेजियम की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उसे कार्यपालिका के दबाव का विरोध करना चाहिए। उनके अनुसार, नियुक्तियों के मामले में सरकार से संवाद करना और सरकार की पूर्व मंजूरी को निर्णय की शर्त बना देना दो अलग स्थितियां हैं। संवाद लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच सामान्य प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन नियुक्तियों के निर्णय में कॉलेजियम की स्वतंत्र भूमिका बनी रहनी चाहिए। कौल की चिंता इस बात को लेकर है कि यदि सरकार की सहमति को औपचारिक निर्णय से पहले अनिवार्य मान लिया गया, तो न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ सकता है।

कौल ने अपने विचारों के समर्थन में वर्ष 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) से जुड़े घटनाक्रम का भी उल्लेख किया।

कन्नड़ लोगों को नौकरी से वंचित किया तो होगी कार्रवाई : शिवकुमार

बंगलूरू। कर्नाटक में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को स्पष्ट किया कि यदि कोई निजी संस्थान जानबूझकर राज्य के कन्नड़ लोगों को नौकरी के अवसरों से वंचित रखता है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कन्नड़ लोगों के अधिकारों, सम्मान और रोजगार के अवसरों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री का यह बयान बंगलूरू की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों में स्थानीय कन्नड़ भाषी लोगों को पर्याप्त रोजगार अवसर नहीं मिलने की शिकायतों के बीच आया है। सरकार ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेने की बात कही है और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई है।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि बंगलूरू की आईटी कंपनियों में स्थानीय कन्नड़ भाषी लोगों को नौकरी के अवसर नहीं दिए जाने से संबंधित शिकायतें सरकार के संज्ञान में आई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें सुनकर दुख होता है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाए और उन्हें अपनी प्रतिभा तथा कौशल के आधार पर आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलें। शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि यदि किसी संस्थान की ओर से जानबूझकर स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार से दूर रखने की बात सामने आती है, तो सरकार इस मामले में उचित कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में कन्नड़ लोगों का सर्वोच्च स्थान है और उनके अधिकारों, सम्मान तथा अवसरों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने राज्य की पहचान और विकास में स्थानीय लोगों के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार उनकी प्रतिभा और क्षमताओं पर गर्व करती है। उनके बयान से यह संकेत मिला कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से जुड़ी शिकायतों को केवल सामान्य शिकायत मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर संबंधित संस्थानों के रवैये की जांच कर कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

बंगलूरू लंबे समय से देश के प्रमुख तकनीकी और आईटी केंद्रों में शामिल रहा है। यहां बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर विकास, स्टार्टअप, डिजिटल सेवाओं और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में शहर ने देश-विदेश में अपनी पहचान बनाई है। इन क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं ने विभिन्न राज्यों के युवाओं को बंगलूरू की ओर आकर्षित किया है। दूसरी ओर, स्थानीय युवाओं के बीच भी यह सवाल उठता रहा है कि राज्य के तेजी से विकसित होते तकनीकी क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं या नहीं। मुख्यमंत्री के ताजा बयान ने इसी बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है।

शिवकुमार ने बंगलूरू को भारत की तकनीकी राजधानी के रूप में मिली पहचान का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य को कन्नड़ लोगों की प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं पर गर्व है। राज्य की आर्थिक प्रगति में स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। रोजगार के अवसर केवल आर्थिक सुरक्षा का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, परिवारों की आय बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में स्थानीय उम्मीदवारों की शिकायतों का समाधान करना सरकार और संबंधित संस्थानों दोनों के लिए महत्वपूर्ण विषय है।

मुख्यमंत्री ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि कार्रवाई की स्थिति तब बनेगी, जब यह पाया जाएगा कि किसी निजी संस्थान ने जानबूझकर कन्नड़ लोगों को रोजगार के अवसरों से दूर रखा है। इसका अर्थ है कि शिकायतों और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर मामले को देखा जाएगा। किसी संस्थान में भर्ती के दौरान उम्मीदवारों की योग्यता, कौशल, अनुभव और पद की आवश्यकताओं जैसी बातों की भी भूमिका होती है। इसलिए स्थानीय उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलने की शिकायतों की जांच करते समय वास्तविक कारणों और भर्ती प्रक्रिया की परिस्थितियों को समझना महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में ऐसी स्थिति में उचित कार्रवाई करने की बात कही है।

कर्नाटक में स्थानीय रोजगार का प्रश्न उद्योगों की जरूरतों और क्षेत्रीय हितों के बीच संतुलन से भी जुड़ा है। बंगलूरू की आईटी कंपनियां देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार देती हैं और यही विविधता शहर के तकनीकी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। वहीं, स्थानीय युवाओं की अपेक्षा है कि उनके राज्य में स्थापित कंपनियों और संस्थानों में उन्हें भी अपनी योग्यता साबित करने के समान अवसर मिलें। इस संदर्भ में सरकार के सामने चुनौती ऐसी व्यवस्था को प्रोत्साहित करने की है, जिसमें स्थानीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षण, कौशल विकास और भर्ती प्रक्रिया तक बेहतर पहुंच मिले तथा उद्योगों की जरूरतें भी प्रभावित न हों।

तकनीकी क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए लगातार बदलते कौशल और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर विकास, डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य उभरते क्षेत्रों में कंपनियां विशेष दक्षता वाले उम्मीदवारों की तलाश करती हैं। ऐसे में स्थानीय युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा संस्थानों, कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्योगों के बीच समन्वय भी उपयोगी हो सकता है। यदि स्थानीय उम्मीदवारों को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिले, तो वे रोजगार के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। साथ ही, कंपनियों की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखना भी जरूरी है। शिवकुमार के बयान के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित रखने संबंधी शिकायतों पर सरकार किस प्रकार आगे बढ़ती है और किन परिस्थितियों में कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने निजी संस्थानों को यह संदेश दिया है कि स्थानीय लोगों के हितों और सम्मान से जुड़े मुद्दों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि, बयान में किसी विशिष्ट कंपनी का नाम या किसी संस्थान के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई का विवरण सामने नहीं आया है। फिलहाल सरकार की ओर से शिकायतों को गंभीरता से लेने और जानबूझकर अवसर रोकने की स्थिति में उचित कदम उठाने की बात कही गई है। कर्नाटक सरकार के इस रुख से स्थानीय रोजगार को लेकर जारी बहस को नई गति मिल सकती है। बंगलूरू जैसे बड़े तकनीकी केंद्र में रोजगार के अवसरों का विस्तार राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं स्थानीय युवाओं की भागीदारी और उनके कौशल का उपयोग भी उतना ही आवश्यक है।

संपादकीय

कहां दिखेगी अब जंतर-मंतर की वह लपक-झपक?

कभी सूरज, चांद और सितारों की चाल समझने वाली जगह आज सत्ता की चाल पर सवाल उठाने वालों का ठिकाना बन गई थी। जंतर-मंतर का नाम आते ही आंखों के सामने धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, पुलिस की भागदौड़, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और कैमरों की चमकती रोशनी का दृश्य उभरने लगता था। यह कोई जादू-टोने का अड्डा नहीं था, जहां छड़ी घुमाकर झोले से कबूतर निकाल दिए जाते हों। कभी यह खगोलीय गणनाओं और ग्रह-नक्षत्रों की गतिविधियों को समझने वाली वेधशाला थी, लेकिन वक्त के साथ इसकी पहचान बदलती चली गई। यहां सरकार की नीतियों पर सवाल उठने लगे, विरोध की आवाजें गूंजने लगीं और लोकतंत्र में असहमति जताने वालों ने इसे अपने संघर्ष का मंच बना लिया। मगर विडंबना देखिए कि सरकार की चाल समझने का दावा करने वाले लोग भी सत्ता की हर चाल को भला कहां समझ पाते हैं! सरकारें अपनी नीतियां बनाती हैं, खुफिया एजेंसियां लोगों की गतिविधियों पर नजर रखती हैं और प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने हिसाब से रणनीति तैयार करता है। दूसरी ओर, जनता भी अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर सड़कों पर उतरती है। लोकतंत्र का यही तो रंग है कि एक तरफ सत्ता होती है, दूसरी तरफ सवाल पूछने वाले नागरिक। दोनों के बीच कभी संवाद होता है, कभी टकराव और कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जिनकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होती। इधर, नई पीढ़ी यानी जेन-ज़ी की सक्रियता ने विरोध-प्रदर्शन की दुनिया को एक नया रंग दे दिया है। यह पीढ़ी अपने सवालों को सोशल मीडिया पर उठाती है, कैमरे के सामने अपनी बात रखती है और कई बार अपने अनोखे अंदाज से प्रशासन को असहज भी कर देती है। पुराने दौर के आंदोलनों में जहां पोस्टर, बैनर और भाषण प्रमुख हुआ करते थे, वहीं आज मोबाइल कैमरे, रील और लाइव वीडियो भी विरोध का हिस्सा बन गए हैं। पुलिस की कार्रवाई हो या प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी, कुछ ही मिनटों में तस्वीरें और वीडियो देशभर में पहुंच जाते हैं। फिर शुरू होती है बहस, आरोप-प्रत्यारोप और घटनाओं की अलग-अलग व्याख्याएं। ऐसे माहौल में जंतर-मंतर जैसे स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी उम्मीद के साथ आता है। कोई अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहता है, कोई किसी फैसले का विरोध करने आया होता है और कोई अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना चाहता है। लेकिन जब किसी स्थान पर लगातार भीड़ जुटने लगे, यातायात और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं सामने आने लगें अथवा प्रशासन को व्यवस्था संभालने में कठिनाई महसूस हो, तो प्रतिबंधों और वैकल्पिक स्थानों की चर्चा भी शुरू हो जाती है। ऐसे में सवाल केवल इतना नहीं रह जाता कि धरना कहां होगा, बल्कि यह भी होता है कि विरोध जताने के लिए नागरिकों को कितनी सहजता से जगह उपलब्ध होगी। जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों की एक अलग ही दुनिया थी। सुबह से ही पुलिसकर्मियों की तैनाती दिखाई देने लगती थी। कहीं प्रदर्शनकारी अपने पोस्टर संभालते नजर आते, कहीं नारेबाजी के बीच अपनी बात रखने की कोशिश करते लोग दिखाई देते और कहीं पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे रहते। कैमरे लिए पत्रकार हर घटनाक्रम पर नजर रखते। कोई पुलिस की कार्रवाई रिकॉर्ड करता, कोई प्रदर्शनकारियों के बयान लेता और कोई पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर डालने की तैयारी करता। देखते ही देखते एक छोटा-सा प्रदर्शन भी चर्चा का विषय बन जाता। कभी-कभी हालात इतने दिलचस्प और तनावपूर्ण हो जाते कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें एक ही तरफ टिक जातीं। पुलिस किसी प्रदर्शनकारी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती, तो बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते। कोई बस की ओर ले जाए जाने का विरोध करता, तो कोई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने लगता। कहीं धक्का-मुक्की होती, कहीं बहस तेज हो जाती और कहीं कैमरे के सामने अपनी बात रखने की होड़ लग जाती। ऐसे दृश्यों को देखकर लगता था मानो जंतर-मंतर केवल विरोध का स्थान नहीं, बल्कि लोकतंत्र के रोजमर्रा के संघर्षों का खुला मंच बन गया हो। अब यदि इस स्थान पर प्रदर्शनों पर रोक लगती है या प्रदर्शनकारियों को दूसरे निर्धारित स्थलों पर जाने के लिए कहा जाता है, तो वहां के नजारे भी बदल जाएंगे। रामलीला मैदान, बुराड़ी या कड़कड़डूमा जैसे वैकल्पिक स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन क्या हर जगह का अपना अलग मिजाज नहीं होता? किसी स्थान की पहचान केवल उसकी भौगोलिक स्थिति से नहीं बनती, बल्कि वहां वर्षों से घटित घटनाओं, आंदोलनों और संघर्षों से भी बनती है। जंतर-मंतर की पहचान भी कुछ ऐसी ही रही है।

फसल संरक्षण व सेहत सुरक्षा हो प्राथमिकता

> "भारत अलनीनो के कारण सर्वाधिक जोखिम वाले देशों में शामिल है। क्लाइमेट ट्रेंड्स के मुताबिक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अलनीनो और जलवायु परिवर्तन का संयुक्त प्रभाव खेती से जुड़े जोखिम बढ़ा रहा है। वर्ष 2050 तक इन दोनों के मिले-जुले प्रभाव से वैश्विक फसल पैदावार आधार स्थिति की तुलना में 10 से 25 प्रतिशत तक घट सकती है।

अलनीनो भयावह खतरे का सबब बनता जा रहा है। दुनिया के मौसम विज्ञानियों ने अलनीनो के खतरनाक स्तर को 'सुपर-डुपर अलनीनो' नाम दिया है। शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, सामान्य वर्षों की तुलना में सुपर-डुपर अलनीनो के कारण अगले छह महीनों में दुनिया भर में करीब 4.51 लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं।

अलनीनो पहले से गर्म होती जलवायु पर अपना असर दिखा रहा है, जिससे आने वाले महीनों में तापमान के रिकॉर्ड टूटने की संभावना बढ़ रही है। इस बार फरवरी में ही गर्मी दस्तक दे सकती है। सुपर अलनीनो के प्रभाव से आने वाले महीनों में वैश्विक स्तर पर सतह का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है। अनुमान है कि अगले 20 वर्षों तक तापमान का यही रुझान देखने को मिल सकता है। विश्व मौसम संगठन की हालिया चेतावनी के मुताबिक, अलनीनो फरवरी 2027 तक बना रह सकता है। ऐसी स्थिति में इसका असर भारत में अगले मानसून की शुरुआत तक रहने की संभावना है। चिंता की बात यह है कि यह सर्दियों की बारिश और तापमान को भी प्रभावित कर सकता है। यही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में तापमान और बारिश के पैटर्न पर भी इसका असर पड़ सकता है। नतीजतन, कहीं सूखे की स्थिति बन सकती है, तो कहीं सामान्य से अधिक बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है।दरअसल, विश्व मौसम संगठन के पूर्वानुमान के मुताबिक, नवंबर महीने में तापमान के चरम पर पहुंचने की संभावना जताई गई थी। लेकिन अब प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास समुद्र का तापमान सामान्य से तीन गुना अधिक है और इसमें तेजी से बढ़ोतरी की आशंका है। समुद्र की गहराई में भी कई हिस्सों में पानी सामान्य से आठ डिग्री तक अधिक गर्म पाया गया है,

जिससे अलनीनो को और ताकत मिली है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के सभी भूभागों में इस साल नवंबर तक सामान्य से अधिक तापमान रहेगा। प्रशांत महासागर का पानी गर्म होने पर भारत की ओर आने वाली हवाओं के दबाव और उनकी दिशा में बदलाव आता है। इससे बादलों की आवाजाही और बारिश का रास्ता भी बदल सकता है। यही अहम कारण है कि प्रशांत महासागर में होने वाला बदलाव भारत जैसे हजारों किलोमीटर दूर स्थित देशों के मौसम को भी प्रभावित करता है।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, अलनीनो का असर केवल मानसून तक सीमित नहीं रहेगा। इसके मजबूत बने रहने पर सर्दियों में भी तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका है। उत्तर भारत में सर्दियों के छोटा होने और फरवरी-मार्च में गर्मी बढ़ने का रुझान पहले से ही देखा जा रहा है। यही नहीं, पश्चिमी विक्षोभ, हिमालय में बर्फबारी और हिंद महासागर की स्थिति की भूमिका भी इसमें काफी महत्त्वपूर्ण होगी। वर्ष 2023-24 के मजबूत अलनीनो ने 2024 को दुनिया का सबसे गर्म साल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक उसी तरह, इस साल भी तापमान का नया रिकॉर्ड बनने का खतरा बना हुआ है।

संभावना है कि दिसंबर महीने में तापमान उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। इससे पहले अलनीनो की स्थिति और तीव्र होगी, जो चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। गौरतलब है कि यह अब तक की सर्वाधिक तापमान वृद्धि होगी। इससे स्पष्ट है कि अलनीनो का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले 2015 में अधिकतम 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। मौसम विज्ञानी रयान माउ का कहना है कि अलनीनो सर्दियों में अपनी अधिकतम शक्ति पर बना रहेगा और अमेरिका को छोड़कर हर जगह वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होगी। प्रभावित क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, जो इतिहास में दर्ज किसी भी पिछले अलनीनो से अधिक है। यह 1950 के बाद से दर्ज की गई सबसे शक्तिशाली मौसमी घटनाओं में से एक हो सकती है। दरअसल, अलनीनो की स्थिति में मानसून कमजोर और अनियमित रहता है। साथ ही, अधिक गर्मी पड़ने से मिट्टी में नमी कम हो जाती है, जिससे खरीफ की फसलों की पैदावार घटने की आशंका रहती है। खरीफ का सीजन सीधे तौर पर देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। धान, मक्का, दालें और तिलहन जैसी प्रमुख फसलें इसी मौसम में बोई जाती हैं। ऐसे में अलनीनो का खतरा केवल मौसम का मुद्दा नहीं है, बल्कि उत्पादन, खाद्य कीमतों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में सबसे बड़ी चिंता उन क्षेत्रों को लेकर है, जहां खेती अब भी बारिश पर निर्भर है।

भारत अलनीनो के कारण सर्वाधिक जोखिम वाले देशों में शामिल है। क्लाइमेट ट्रेंड्स के मुताबिक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अलनीनो और जलवायु परिवर्तन का संयुक्त प्रभाव खेती से जुड़े जोखिम बढ़ा रहा है। वर्ष 2050 तक इन दोनों के मिले-जुले प्रभाव से वैश्विक फसल पैदावार आधार स्थिति की तुलना में 10 से 25 प्रतिशत तक घट सकती है।

इस संबंध में एम्स के एक संकाय सदस्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि हर परिस्थिति और हर स्तर पर हीट एक्शन प्लान लागू करने जैसी रणनीतियों पर तत्काल काम करने की जरूरत है। उनके अनुसार, बुजुर्गों, पहले से बीमार लोगों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और खुले में काम करने वाले श्रमिकों जैसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देना जरूरी है।

चूंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए ऐसे हालात से निपटने के लिए मौसमी पूर्वानुमानों के आधार पर बुआई से पहले फसलों में बदलाव किए जाने चाहिए। राज्यों में सूखा घोषित करने की प्रक्रिया सरल बनाई जानी चाहिए। कृषि योजनाओं में बहुवर्षीय जलवायु जोखिम मॉडल को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, दीर्घकालिक विकास की क्षमता बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था के ढांचे को मजबूत करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

प्रेरणा

साहित्य के सरोकारों से संवाद करती सुभाष रस्तोगी की नई आलोचना-कृति

साहित्य अपने समय का दस्तावेज होने के साथ समाज की चेतना, संवेदना और विचारधारा को समझने का सशक्त माध्यम भी है। किसी रचना का महत्व केवल उसकी भाषा और शिल्प तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि वह अपने दौर के सवालों को किस गहराई से उठाती है। साहित्यकार की साधना में अध्ययन, अनुभव और वैचारिक संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी उसके सृजन की गति को रोक नहीं पातीं। वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोचक सुभाष रस्तोगी इसका उदाहरण हैं। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बावजूद उनका लेखन लगातार जारी है। उनकी 51वीं पुस्तक 'साहित्य विमर्श के आयाम' आलोचना-कृति के रूप में प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक हिंदी साहित्य की विविध प्रवृत्तियों, भाषा के बदलते स्वरूप, सामाजिक चेतना और क्षेत्रीय साहित्य की उपेक्षित धरोहरों पर विचार करने का अवसर देती है।

सुभाष रस्तोगी का साहित्यिक सफर लंबे समय से आलोचना और साहित्यिक मूल्यांकन की परंपरा से जुड़ा रहा है। उनकी पूर्व प्रकाशित पुस्तकों में 'विष्णु प्रभाकर का साहित्य', 'परिक्रमा', 'चिंतन के वातायन', 'विमर्श और विमर्श', 'कालजयी रचनाएं', 'साक्षात्कार' तथा 'हरियाणा हिंदी साहित्य के निर्माता मोहन चोपड़ा' शामिल हैं। लेखक के अनुसार, 'साहित्य विमर्श के आयाम' आलोचना के क्षेत्र में उनकी सातवीं पुस्तक है। उनकी रचनात्मक यात्रा का विस्तार इस बात को रेखांकित करता है कि साहित्यिक आलोचना किसी कृति की प्रशंसा या कमियां गिनाने भर का कार्य नहीं, बल्कि उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक संदर्भों को सामने लाने की प्रक्रिया है।

दो खंडों में व्यवस्थित इस पुस्तक का पहला भाग साहित्य और भाषा से जुड़े छह महत्वपूर्ण आलेखों का संग्रह है। इनमें स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य की भूमिका, हिंदी कहानी का विकास, हिंदी कविता का राष्ट्रीय परिदृश्य, हरियाणा की लंबी कविता, समकालीन हिंदी आलोचना तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की उपयोगिता जैसे विषय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इक्कीसवीं सदी में हिंदी की स्थिति और संभावनाओं पर भी विचार किया गया है। इन आलेखों के माध्यम से लेखक साहित्य की यात्रा को अलग-अलग संदर्भों में समझने की कोशिश करते हैं। यहां भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक चेतना के निर्माण का माध्यम भी बनकर सामने आती है।

स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य की भूमिका का प्रश्न भारतीय साहित्यिक परंपरा को समझने के लिए विशेष महत्व रखता है। लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देशवासियों में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और सामाजिक जागरूकता की भावना को मजबूत किया। साहित्य ने तत्कालीन परिस्थितियों को दर्ज करने के साथ लोगों को अन्याय और शोषण के विरुद्ध सोचने की प्रेरणा भी दी। इसी तरह हिंदी कहानी ने समय के साथ समाज में आए बदलावों को अपने कथ्य में स्थान दिया। पारिवारिक संबंधों, सामाजिक विषमता, आर्थिक संघर्षों और व्यक्ति की मनःस्थितियों को अभिव्यक्त करते हुए कहानी की विषयवस्तु लगातार विस्तृत हुई है। पुस्तक में इन बदलावों को साहित्यिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया गया है।

सामाजिक न्याय और दलित विमर्श से जुड़े संदर्भ इस कृति को एक व्यापक वैचारिक आधार प्रदान करते हैं। हिंदी साहित्य में वंचित समुदायों की पीड़ा, सामाजिक भेदभाव और समानता के सवालों पर चर्चा समय के साथ अधिक व्यापक हुई है। हालांकि, इन विषयों से जुड़ी संवेदनाएं उन रचनाओं में भी दिखाई देती हैं, जिनकी रचना उस समय हुई थी, जब आज प्रचलित विमर्श की शब्दावली व्यापक रूप से सामने नहीं आई थी। इस संदर्भ में राजेंद्र यादव की भूमिका और मनु भंडारी की पुस्तक 'एक कहानी यह भी' का उल्लेख किया गया है। साथ ही सियारामशरण गुप्त की रचना 'एक फूल की चाह' की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव की पीड़ा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मंदिर से फूल लाने तक पर प्रतिबंध का प्रसंग उस सामाजिक मानसिकता को उजागर करता है, जिसमें व्यक्ति की गरिमा पर जन्म और जातिगत पहचान के आधार पर प्रश्न खड़े किए जाते थे। यह उदाहरण साहित्यिक आलोचना के एक महत्वपूर्ण पक्ष को सामने लाता है। किसी रचना का मूल्यांकन करते समय उसके रचनाकाल की परिस्थितियों, लेखक की दृष्टि और उसके कथ्य में निहित सामाजिक चेतना को समझना आवश्यक होता है। कई बार बाद में स्थापित हुए विमर्शों के मूल तत्व पुरानी रचनाओं में मौजूद मिलते हैं। इस प्रकार आलोचना अतीत के साहित्य को वर्तमान के प्रश्नों से जोड़ती है और पाठकों को स्थापित धारणाओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित करती है।

पुस्तक का दूसरा खंड 'साहित्य विमर्श के आयाम : वाया कृति विमर्श' हरियाणा और पंजाब के साहित्य को केंद्र में रखता है। इसमें दोनों राज्यों की 56 पुस्तकों पर समीक्षात्मक दृष्टि और आलेख संकलित हैं। सुभाष रस्तोगी के लिए हरियाणा जन्मभूमि है और पंजाब कर्मभूमि रहा है। इन दोनों क्षेत्रों से उनका व्यक्तिगत और साहित्यिक जुड़ाव इस खंड को विशेष अर्थ प्रदान करता है। क्षेत्रीय साहित्य पर केंद्रित लेखन के माध्यम से वे ऐसी पुस्तकों और रचनाकारों की ओर भी पाठकों का ध्यान खींचते हैं, जिन्हें व्यापक साहित्यिक मंचों पर अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया। यह प्रयास हिंदी साहित्य के इतिहास को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में दिवंगत कवि भगवत रावत की लंबी मुक्तछंद कविताओं से जुड़ा प्रसंग उल्लेखनीय है। लेखक के अनुसार, इन रचनाओं से संबंधित सामग्री प्राप्त करने के लिए संपर्क करने पर अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली। बाद में अभिलेखागार से एक लेख मिला, लेकिन उसकी स्थिति खराब थी। यह प्रसंग साहित्यिक दस्तावेजों के संरक्षण से जुड़ी गंभीर चुनौती को सामने लाता है। अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं, पत्र, आलेख और पांडुलिपियां उचित देखभाल के अभाव में धीरे-धीरे नष्ट होने लगती हैं। इनके संरक्षण के लिए व्यवस्थित अभिलेखागार, पुस्तकालयों और साहित्यिक संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्यिक विरासत को बचाना केवल अतीत को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि भविष्य के शोध और आलोचना के लिए आधार तैयार करना भी है। सुभाष रस्तोगी इन दिनों 'आधी हकीकत, आधा फसाना' लिखने की तैयारी कर रहे हैं।

Trump ने मस्क-CIA को ही कर दिया एक्सपोज? राहुल की वियतनाम यात्रा की पोल भी खुल गई!

इस वक्त अमेरिका के अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी तरफ हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। दोनों एक ही देश के हैं। दोनों मतलब एलन मस्क ट्रंप की पार्टी का समर्थन करते हैं और ट्रंप के समर्थक भी हैं एलन मस्क। 2024 के चुनाव में भी अच्छी खासी फंडिंग की थी और इस वाले चुनाव में भी हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग की है और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है यूक्रेन। अमेरिका के भीतर महंगाई बढ़ रही है क्योंकि डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। स्टेट ऑफ होर्मुज बंद है। बाब अल मंदेब बंद है। जिसकी वजह से रूस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा और वहां से तेल मंगाना पड़ा। अब रूस की रिफाइनरीज के ऊपर यूक्रेन हमले कर रहा है। यूक्रेन हमले कर रहा है। जिन ड्रोन से उन ड्रोन पर स्टालिंग की डिवाइस लगी हुई है। उस डिवाइस की मदद से ही यूक्रेन के ड्रोन रशिया को छेद पा रहे हैं। उसकी रिफाइनरी पर हमला कर पा रहे हैं। ऐसे में आपने पिछले दिनों खबर सुनी कि किस तरीके से स्टार लिंक ने यूक्रेन की स्पीड कम कर दी। आप जो समझते हैं ना डाउनलोडिंग करने की स्पीड इंटरनेट की या फिर कुछ सर्च करने की स्पीड सिर्फ वही स्पीड इंटरनेट की नहीं होती है। हथियारों की एक अलग तरीके की स्पीड होती है। 100 किमी प्रति घंटा 150 किमी प्रति घंटा 200 किमी प्रति घंटा तक की स्पीड होती है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा दिक्कत सामने वाले देश को उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में आएंगी। यहां स्टालिंग की स्पीड बहुत ज्यादा थी। लगभग 200 कि.मी. प्रति घंटा के आसपास थी। तो रशिया के इंटरसेप्टर उन्हें पकड़ नहीं पाते थे और ये ड्रोंस जाकर रिफाइनरीज को हिट कर रहे थे। ट्रंप को रूस के साथडील करनी थी। ऐसे में अब उन्होंने आदेश दिया या नहीं दिया। ऐसे में अचानक से यूक्रेन की स्पीड इंटरनेट वाली कम हो गई। आरोप लगा कि मस्क ने यूक्रेन के मिलिट्री स्टालिंग की स्पीड को 100 मील प्रति घंटा पर कैप कर दिया। मतलब 100 मील प्रति घंटा का मान लीजिए कि 160 किमी प्रति घंटे के हिसाब से कैप कर दिया। कैप करने का मतलब है अगर वो ड्रोन 160 कि.मी. प्रति घंटा की स्पीड से ऊपर जाएगा तो वो उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगी। उसका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो टूट जाएगा। जाएगा। अब जब इंटरनेट कनेक्शन टूट जाएगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि कहां हिट करना है, कहां हिट नहीं करना है। और जो उसे ऑपरेट कर रहे हैं लोग उनके पास तक वीडियो जब नहीं पहुंचेगा तब वो लोग भी एक तरीके से अंधे हो जाएंगे। तो ये पूरा गेम किया गया।इससे यूक्रेन के हमलावर ड्रोन रूस के सामने फेल होने लगे और अब वॉल स्ट्रीट जनरल की ब्रेकिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने खुद मस्क को फोन करके कहा कि यह पाबंदी हटा लो। ट्रंप का कहना है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। एलन मस्क का कहना है कि मेरा भी उसमें कोई रोल नहीं है। रोल सामने आया सीआईए का। स्टार लिंक से डायरेक्ट इंटरनेट नहीं लेता है यूक्रेन। ये लेता है स्टार शील्ड से। स्टार शील्ड के ऊपर मतलब कौन नजर रखता है या फिर किसके हाथ में स्टार शील्ड है। स्टार शील्ड हाथ में है सीआईए के। अब पूरा गेम आपको समझ आया आ गया होगा कि किस तरीके से सिर्फ एक खबर बाहर आने से कि ट्रंप ने खुद मस्क को फोन करके कहा कि यह पाबंदी हटा लो। यहां सीआईए का भी जो पर्दाफाश हो गया और एलन मस्क भी एक्सपोज हो गए। वॉल स्ट्रीट जनरल के मुताबिक यह फोन बुधवार को किया गया। ट्रंप ने मस्क से कहा कि वो इस स्पीड लिमिट से नाराज हैं। यह लिमिट 14 अक्टूबर को स्पेस एक्स ने लगाई थी। यूक्रेन को शक है कि ट्रंप ने रूस की तरफ झुकाव का हिस्सा था। क्योंकि पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने मॉस्को से तेल खरीदने और जेलस्की को हटाने की बात कही थी। कारनेगी एंडोमेंट के एक्सपर्ट माइकल कॉफमैन का कहना है कि अगर यह थ्रटल नहीं हटा तो रूस का फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ना फिर तेज हो जाएगा। मतलब यूक्रेन की जंग का रिमोट कंट्रोल आज भी एक प्राइवेट कंपनी और दो लोगों के फोन कॉल पर टिका हुआ है। ट्रंप अब कतई नहीं चाहते कि जेलस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति रहे और वो उन्हें हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतिहासजानें

दो हफ्ते पहले तक राहुल गांधी देश में चुनाव चोरी, वोट चोरी, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा इन सब की मांग कर रहे थे। संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने के आरोप बीजेपी और सरकार पर वह लगा रहे थे। पूरा विपक्ष एक साथ आ गया था। सिर्फ आरोप नहीं लगाया जा रहा था। दिल्ली में आकाशवाणी से लेकर राजघाट तक, राष्ट्रपति भवन से लेकर जंतरमंतर तक जमकर प्रदर्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालकर सरकार और पूरे संवैधानिक सिस्टम पर सवाल खड़े करने की कोशिश हुई। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना हर विपक्षी का अधिकार है। सरकार ट्रैक पर रहे यह याद दिलाना विपक्ष का काम है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को इस तरीके से डिसक्रेडिट कर देना कहां तक जायज है? राहुल गांधी ने देश में बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दिया था। सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। बीजेपी, सरकार और बाकी तमाम को आकर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना पड़ रहा था हर चीज पर। लेकिन जैसे ही इस पूरे सियासी गेम में पीएम मोदी की एंट्री हुई पूरा समीकरण 360 डिग्री चेंज हो गया। पूरा सिस्टम ऐसे पलटा कि अब बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। यह सब बदला है।

अभियान

कर्मों की गूंज लौटकर आती है, जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे

मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। हमारे विचार, व्यवहार और निर्णय न केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं, बल्कि आने वाले समय की दिशा भी निर्धारित करते हैं। जीवन में सुख और दुःख का अनुभव हर व्यक्ति करता है, लेकिन अक्सर मन में यह प्रश्न उठता है कि अच्छे कर्म करने वाले लोगों को भी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है और गलत कार्य करने वाले कुछ लोग लंबे समय तक सुख-सुविधाओं में कैसे जीवन बिताते हैं। क्या कर्मों का फल तुरंत मिलता है या उसके लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है? क्या कर्मों का परिणाम केवल इसी जीवन तक सीमित है या उसका संबंध अगले जन्म से भी है? भारतीय दर्शन में इन प्रश्नों पर गहराई से विचार किया गया है। श्रीमद्भगवद्गीता का कर्मयोग हमें समझाता है कि मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, लेकिन उन कर्मों के परिणाम अनेक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। इसलिए जीवन में सही मार्ग चुनना और कठिन समय में भी अपने कर्तव्य से पीछे न हटना अत्यंत आवश्यक है।

महाभारत के युद्धक्षेत्र में अर्जुन के मन में भी जीवन, धर्म और कर्म को लेकर अनेक प्रश्न उठे थे। भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें ज्ञान देते हुए कर्म की महत्ता समझाई। एक प्रेरक दृष्टांत के माध्यम से इस विचार को समझा जा सकता है। अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा, "हे माधव! संसार में लोग कहते हैं कि पुण्य करने से सुख और पाप करने से दुःख मिलता है। लेकिन कई बार अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को कष्ट सहना पड़ता है, जबकि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति सुखी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कर्मों का फल केवल अगले जन्म में मिलता है या मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम इसी जीवन में भी भुगतना पड़ता है?"

श्रीकृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर कहा, "हे पार्थ! कर्म का संबंध केवल उसके परिणाम से नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य, प्रभाव और उससे उत्पन्न परिस्थितियों से भी होता है। प्रत्येक कर्म अपने साथ एक प्रभाव लेकर आता है। कुछ कर्मों का परिणाम तुरंत सामने आ जाता है, कुछ का प्रभाव समय बीतने के साथ दिखाई देता है और कुछ कर्मों के परिणाम इतने व्यापक होते हैं कि उन्हें समझने के लिए मनुष्य को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए किसी व्यक्ति के जीवन की केवल एक घटना देखकर उसके कर्मों का पूरा हिसाब नहीं लगाया जा सकता।"

इसके बाद श्रीकृष्ण ने अर्जुन को एक दृष्टांत सुनाया। एक गांव में दो यात्री रहते थे। एक रात दोनों किसी आवश्यक कार्य से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। मार्ग में कहीं ऊबड़-खाबड़ जमीन थी, कहीं गड्ढे थे और कहीं पत्थर बिखरे पड़े थे। दोनों यात्रियों के पास एक-एक दीपक था। पहले यात्री ने अपने दीपक को जलाया और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। दीपक की रोशनी में उसे रास्ते की बाधाएं दिखाई देने लगीं। वह गड्ढों से बचकर चलता और दूसरों को भी सावधान करता जाता था।

उसके साथ कुछ और राहगीर भी चल रहे थे। जब उन्होंने दीपक की रोशनी देखी, तो वे भी उसी के पीछे सुरक्षित आगे बढ़ने लगे। उस यात्री की सावधानी से केवल उसका अपना रास्ता ही आसान नहीं हुआ, बल्कि दूसरे लोगों को भी सहायता मिली। उसने अपनी रोशनी को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों को भी रास्ता दिखाया। इस प्रकार एक छोटा-सा दीपक अंधकार से भरे मार्ग पर कई लोगों के लिए सहारा बन गया।

दूसरा यात्री यह सब देखकर हंसने लगा। उसने कहा, "तुम व्यर्थ ही अपने दीपक में तेल खर्च कर रहे हो। इतनी छोटी-सी रोशनी से क्या लाभ होगा? रास्ता तो पैरों से ही तय करना है। दीपक जलाने से कौन-सा मंजिल जल्दी आ जाएगी?" इतना कहकर उसने अपने दीपक की लौ बुझा दी और बिना रोशनी के आगे बढ़ने लगा। उसे लगा कि वह भी उसी गति से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा और दीपक जलाए रखने की परेशानी से बच जाएगा।

कुछ दूर चलने के बाद रास्ता और कठिन हो गया। अंधकार इतना गहरा था कि जमीन पर पड़े पत्थर और गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरे यात्री ने अनुमान के आधार पर कदम बढ़ाया, लेकिन उसका पैर एक गहरे गड्ढे में जा पड़ा। वह संतुलन खोकर गिर गया और उसे गंभीर चोट लग गई। दर्द से कराहते हुए उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। जिस दीपक को वह बेकार समझ रहा था, वही उसकी सुरक्षा का साधन बन सकता था।

पहला यात्री कुछ दूरी पर पहुंच चुका था। जब उसने पीछे से आवाज सुनी, तो वह अपने साथियों को लेकर वापस लौटा। उसने अपने दीपक की रोशनी से घायल यात्री को देखा, उसे उठाया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में सहायता की। दूसरे यात्री ने लज्जित होकर कहा, "मैंने तुम्हारी बात का मजाक उड़ाया और अपनी रोशनी स्वयं बुझा दी। यदि मैं दीपक जलाए रखता, तो शायद इस परेशानी से बच जाता।"

श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, "हे पार्थ! इस दृष्टांत में दीपक केवल मिट्टी का पात्र और तेल की लौ नहीं है। यह मनुष्य के विवेक, सद्बुद्धि और अच्छे कर्मों का प्रतीक है। जो व्यक्ति सत्य, दया, ईमानदारी और परोपकार का मार्ग अपनाता है, वह अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश बनाए रखता है। उसके निर्णय अधिक विवेकपूर्ण होते हैं और उसके कार्य दूसरों के लिए भी लाभकारी बन सकते हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अहंकार, स्वार्थ, छल और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले कार्यों में लगा रहता है, वह धीरे-धीरे अपने विवेक की रोशनी को कमजोर करता जाता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार अपनी गलतियों का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके कर्म उसके व्यवहार, संबंधों और भविष्य की परिस्थितियों को प्रभावित करने लगते हैं।"

अर्जुन ने फिर पूछा, "हे केशव! यदि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति भी कठिनाइयों से घिर जाए, तो उसे क्या समझना चाहिए? क्या उसके पुण्य कर्म व्यर्थ हो गए?" श्रीकृष्ण ने समझाया, "नहीं पार्थ! कठिनाई का आना इस बात का प्रमाण नहीं है कि अच्छे कर्म निष्फल हो गए। जीवन में अनेक परिस्थितियां एक साथ काम करती हैं। किसी व्यक्ति को बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, किसी को आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है और किसी को अपने प्रियजनों से बिछड़ने का दुःख सहना पड़ सकता है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच उसका सदाचार, धैर्य और विवेक उसे टूटने से बचा सकता है। अच्छे कर्म हमेशा यह सुनिश्चित नहीं करते कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि वे कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और सही दिशा प्रदान करते हैं।"

श्रीकृष्ण के इस संदेश का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि कर्म का मूल्य केवल उसके बाहरी परिणाम से निर्धारित नहीं होता। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना और किसी के अधिकारों का सम्मान करना ऐसे कार्य हैं, जिनका प्रभाव तत्काल दिखाई न देने पर भी समाज में विश्वास और सद्भाव बढ़ाता है। इसके विपरीत, झूठ बोलकर लाभ प्राप्त करना, किसी का हक छीनना या अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना कुछ समय के लिए लाभदायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन इससे विश्वास टूटता है और संबंधों में दूरी पैदा होती है। व्यक्ति को अपने किए हुए कार्यों के कारण अपराधबोध, तनाव और पश्चाताप का सामना भी करना पड़ सकता है। आज के जीवन में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। विद्यार्थी यदि नियमित अध्ययन करता है, तो उसकी मेहनत ज्ञान और आत्मविश्वास के रूप में सामने आती है। किसान यदि उचित समय पर बीज बोता है और फसल की देखभाल करता है, तो उसे बेहतर उपज मिलने की संभावना बढ़ती है। व्यापारी ईमानदारी से व्यवहार करता है, तो ग्राहकों का विश्वास अर्जित कर सकता है। परिवार में प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी का व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाता है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) ,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

जयपुर में किसानों के खेतों पर चोरों का धावा, 150 सिंचाई फव्वारे गायब

जयपुर। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के खेत अब चोरों के निशाने पर हैं। बस्सी इलाके के फालियावास और गुड़ावास गांवों में सिंचाई के उपकरण चोरी होने की लगातार सामने आ रही घटनाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में चोर खेतों से करीब 150 सिंचाई फव्वारे, बिजली के उपकरण और लगभग 200 फीट विद्युत केबल चोरी कर चुके हैं। बीती रात भी 38 से अधिक सिंचाई फव्वारे चोरी होने का आरोप लगाया गया है। लगातार हो रही इन वारदातों से किसानों में नाराजगी है। उनका कहना है कि खेतों में मेहनत से तैयार की गई खेती को पानी देने के लिए जिन उपकरणों की जरूरत होती है, उन्हीं को निशाना बनाकर उनकी आर्थिक परेशानी बढ़ाई जा रही है। किसानों ने कानोता थाना पुलिस से चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने और चोरी हुआ सामान बरामद कराने की मांग की है।

ग्रामीण क्षेत्र में खेती-किसानी पहले ही मौसम, पानी और बढ़ती लागत जैसी चुनौतियों से जूझती है। ऐसे में खेतों से सिंचाई के उपकरणों का बार-बार गायब होना किसानों के लिए नई परेशानी बन गया है। फालियावास और गुड़ावास गांवों के किसानों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से चोर लगातार खेतों को निशाना बना रहे हैं। उनका आरोप है कि अब तक सात से आठ बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। इन वारदातों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले फव्वारे, बिजली से जुड़े उपकरण और विद्युत केबल चोरी किए जाने की बात सामने आई है। किसानों का कहना है कि चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे खेतों में सामान छोड़कर जाना भी उनके लिए चिंता का विषय बन गया है।

किसानों के दावे के अनुसार, अब तक करीब 150 सिंचाई फव्वारे चोरी हो चुके हैं। इसके अलावा दो डीपीओ और लगभग 200 फीट विद्युत केबल गायब होने की बात भी कही जा रही है। बीती रात की घटना में 38 से अधिक फव्वारे चोरी होने का आरोप है। हालांकि, चोरी हुए सामान की पूरी सूची, उसकी कुल कीमत और सभी घटनाओं में हुए नुकसान का आधिकारिक आंकड़ा फिलहाल सामने नहीं आया है। इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि भी आवश्यक है। फिर भी किसानों की ओर से बताई जा रही घटनाओं ने इलाके में खेतों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सिंचाई फव्वारे खेती के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इनकी मदद से खेतों तक पानी पहुंचाने और फसलों की जरूरत के अनुसार सिंचाई करने में सुविधा मिलती है। किसान अपनी जरूरत और खेत की स्थिति के मुताबिक इन उपकरणों की व्यवस्था करते हैं। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में फव्वारे चोरी हो जाते हैं, तो सिंचाई व्यवस्था को दोबारा सुचारु करने के लिए किसानों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। बिजली के उपकरण और केबल भी सिंचाई व्यवस्था से जुड़े होने के कारण महत्वपूर्ण हैं। इनके गायब होने से न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि खेतों में पानी पहुंचाने का काम भी प्रभावित होने की आशंका रहती है। किसानों का कहना है कि खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जुटाने के लिए उन्हें काफी मेहनत और पैसा लगाना पड़ता है। फसल तैयार करने की प्रक्रिया में बीज, खाद, बिजली, पानी और मजदूरी सहित कई मदों पर खर्च होता है। ऐसे में उपकरणों की चोरी उनके लिए दोहरी मार साबित हो सकती है। एक तरफ चोरी हुए सामान को दोबारा खरीदने का खर्च उठाना पड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर सिंचाई में देरी होने पर फसल की देखभाल भी प्रभावित हो सकती है। यदि समय पर खेतों में पानी नहीं पहुंचता है, तो फसलों की स्थिति पर भी असर पड़ने की आशंका रहती है। यही वजह है कि किसान इन घटनाओं को केवल सामान चोरी होने की घटना नहीं, बल्कि खेती-किसानी से जुड़ी गंभीर समस्या के रूप में देख रहे हैं।

लगातार हो रही वारदातों ने ग्रामीण इलाकों में खेतों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। कई खेत आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थित होते हैं, जहां रात के समय लोगों की आवाजाही कम रहती है। ऐसे स्थानों पर रखे उपकरणों की निगरानी करना किसानों के लिए आसान नहीं होता। किसान दिनभर खेतों में काम करने के बाद घर लौट जाते हैं, जबकि सिंचाई से जुड़े कई उपकरण खेतों में ही लगे या रखे रहते हैं। ऐसे में रात के समय चोरी की आशंका बनी रहती है। हालांकि, फालियावास और गुड़ावास में हुई घटनाओं में किन लोगों की भूमिका है और चोरी का सामान किस रास्ते ले जाया गया, इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा।

किसानों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि उनके अनुसार बार-बार चोरी होने के बावजूद वारदातों पर रोक नहीं लग पा रही है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो चोर आगे भी खेतों को निशाना बना सकते हैं। इससे किसानों को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्रामीणों की मांग है कि चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित खेतों और आसपास के क्षेत्रों में रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। साथ ही, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाए और घटनास्थलों से मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाए।

लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद किसानों ने कानोता थाना पुलिस से हस्तक्षेप की मांग की है। किसानों की अपेक्षा है कि पुलिस शिकायतों के आधार पर घटनाओं की जांच करे, चोरी हुए सामान का पता लगाए और वारदातों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करे। चोरी गए फव्वारों, बिजली के उपकरणों और केबल की बरामदगी से किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में नियमित गश्त और किसानों के साथ समन्वय स्थापित करने से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है।

फिलहाल, फालियावास और गुड़ावास में किसानों की ओर से सामने आए चोरी के दावों ने खेतों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। करीब 150 सिंचाई फव्वारे चोरी होने और बीती रात 38 से अधिक फव्वारे गायब होने के आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन वारदातों को अंजाम कौन दे रहा है और चोरी का सामान कहां खपाया जा रहा है। इन सवालों का जवाब पुलिस जांच से ही मिल सकेगा। किसानों को उम्मीद है कि पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी, चोरी की घटनाओं का खुलासा होगा और उनकी मेहनत से जुटाए गए उपकरण वापस मिल सकेंगे।

पश्चिम रेलवे के PCCM श्री तरुण जैन ने सोमनाथ, वेरावल सहित विभिन्न स्टेशनों का किया संरक्षा निरीक्षण, यात्री सुविधाओं एवं वाणिज्यिक गतिविधियों की समीक्षा

भावनगर मंडल में यात्री सुविधाओं के उन्नयन, स्टेशन व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (PCCM) श्री तरुण जैन ने 24 अक्टूबर, 2026 को सोमनाथ, वेरावल, मालिया हाटीना एवं आद्री रोड रेलवे स्टेशनों का संरक्षा निरीक्षण किया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान श्री जैन ने स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं, वाणिज्यिक व्यवस्थाओं तथा स्टेशन परिसर की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर यात्री सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को बेहतर बनाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई।

प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (PCCM) श्री तरुण जैन ने सोमनाथ स्टेशन पर जो कार्य प्रगति पर है उसकी समीक्षा की एवं उन्होंने समीक्षा पश्चात यात्री सुविधा हेतु वाणिज्यिक गतिविधी को देखते हुए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

श्री जैन ने सोमनाथ रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण के पश्चात GHCL लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट (मटेरियल) के साथ बैठक की। बैठक में रेलवे एवं उद्योग के बीच बेहतर समन्वय, माल यातायात की संभावनाओं तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

इसके पश्चात उन्होंने वेरावल, मालिया हाटीना एवं आद्री रोड रेलवे स्टेशनों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य स्टेशन सुविधाओं एवं वाणिज्यिक कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए रेलवे सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास करना था। पश्चिम रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने, स्टेशनों की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा उद्योगों के साथ समन्वय के माध्यम से माल यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

सूरत में एआईसीसी पर्यवेक्षक मोहन जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस: 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान की घोषणा

(निर्भीक, निष्पक्ष एवं तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा) सूरत

देश में लोकतंत्र और नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए "वोट बचाओ, देश बचाओ" अभियान के अंतर्गत सूरत सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एआईसीसी पर्यवेक्षक और महाराष्ट्र के पूर्व विधायक श्री मोहन जोशी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला।

ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आंदोलन की तैयारी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहन जोशी जी ने कहा, "कांग्रेस ने देश के प्रत्येक नागरिक के मतदान अधिकार की रक्षा करने और मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए गए लोगों के नाम पुनः दर्ज कराने के लिए राष्ट्रव्यापी संघर्ष का बिगुल बजा दिया है।" उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इस आंदोलन को ब्लॉक स्तर से लेकर जिला, राज्य और अखिल भारतीय स्तर तक तेज करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

दो महीने के अभियान के लिए कार्य योजनाः

घर-घर जाकर जनसंपर्क अभियानः अगले दो महीनों तक 'लोकतंत्र बचाओ' विषय के अंतर्गत पर्चे बांटकर व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मतदाता सूचियों का सत्यापनः कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाता सूचियों के साथ घर-घर जाएंगे और उन परिस्थितियों की गहन जांच करेंगे जिनके तहत नागरिकों के नाम हटाए गए हैं और उनके नाम बहाल करने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी करेंगे।

चोपाल सभाः आने वाले दिनों में, लोगों को जागरूक करने और वोट चोरों का पर्दाफाश करने के लिए प्रत्येक वार्ड में 'चोपाल सभा' का आयोजन किया जाएगा।

1 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का विरोध प्रदर्शन होगा।

मोहन जोशी जी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 नवंबर को दिल्ली में एक विशाल राष्ट्रीय स्तर का विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। सूरत से बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दिल्ली जाएंगे।

सूरत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर के कई शीर्ष पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनमें क्षेत्रीय प्रवक्ता नैशाध देसाई, सूरत नगर कांग्रेस अध्यक्ष विपुल उधनावाला, संगठन के महासचिव रोहित सावलिया, पार्षद अरशद जरीवाला, पूर्व पार्षद असलम सैकलवाला, प्रवक्ता किरण रायका, छाया ठाकुर और सह-कोषाध्यक्ष नीरव राणा शामिल थे।

भारतीय रेल की वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का लाभ अब पीआरएस काउंटरों पर आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी मिलेगा

भारतीय रेल अपनी मौजूदा वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (ओटीआईएस) का विस्तार करते हुए 27 अक्टूबर, 2026 से अपने पूरे नेटवर्क में यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों पर आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी यह सुविधा प्रदान करेगी। आईआरसीटीसी के माध्यम से ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध यह योजना अब रेलवे आरक्षण काउंटरों से आरक्षित टिकट खरीदने वाले पात्र यात्रियों के लिए भी उपलब्ध होगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बीमा सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक होगी। यह सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों को प्रदान की जाएगी जो बीमा का विकल्प चुनेंगे, मोबाइल नंबर देंगे और डिजिटल माध्यम से भुगतान करेंगे। लागू बीमा प्रीमियम टिकट किराये के साथ लिया जाएगा तथा किराये और प्रीमियम, दोनों का भुगतान

केवल डिजिटल माध्यम से करना होगा। लागू नियमों एवं शर्तों के अनुसार, प्रीमियम सभी करों सहित प्रति यात्री 45 पैसे है। यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिनके टिकट की स्थिति बुकिंग के समय कन्फर्म, आरएसी या आंशिक रूप से कन्फर्म हो। बीमा का विकल्प चुने जाने पर यह एक ही पीएनआर के अंतर्गत बुक किए गए सभी पात्र यात्रियों पर लागू होगा। पाँच वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों की बुकिंग बिना बर्थ/सीट के की गई हो, वे बीमा के अंतर्गत कवर नहीं होंगे, जबकि पाँच से ग्यारह वर्ष की आयु के बच्चे बर्थ के साथ या बिना बर्थ के भी पात्र होंगे।

पॉलिसी के अंतर्गत आने वाली रेल दुर्घटना या अप्रिय घटना की स्थिति में इस योजना के तहत मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता के लिए 10 लाख, स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए 7.50 लाख तक तथा चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने के खर्च के लिए 2 लाख तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अधीन पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए 10,000 का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

यात्रियों को यात्रा बीमा संबंधी अपना विकल्प अंकित करने की सुविधा देने के लिए आरक्षण मांग प्रपत्र में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रपत्र पश्चिम रेलवे के सभी पीआरएस केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इन केंद्रों पर यात्रियों को इस सुविधा तथा इसके लिए डिजिटल भुगतान और मोबाइल नंबर की आवश्यकता के बारे में जानकारी देने हेतु उद्घोषणाएं भी की जाएंगी। आरक्षण कर्मचारी यात्रियों को बीमा के विकल्प और निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन देंगे।

बीमा पॉलिसी का विवरण यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यात्रियों को बुकिंग के बाद उपलब्ध कराए गए लिंक का उपयोग करके संबंधित बीमा कंपनी की वेबसाइट पर नामांकन संबंधी विवरण भरना चाहिए। मृत्यु संबंधी दावों का निपटान घोषित नामित व्यक्ति के पक्ष में किया जाएगा अथवा नामित व्यक्ति का विवरण दर्ज न होने पर विधिक वारिस प्रमाणपत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर विधिक वारिसों के पक्ष में किया जाएगा। योजना के मौजूदा नियम एवं शर्तें पीआरएस काउंटरों से की गई बुकिंग पर भी लागू होंगी। पॉलिसी जारी करने और दावों के निपटान की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी।

इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक यात्रियों से अनुरोध है कि वे संशोधित आरक्षण मांग प्रपत्र में अपना विकल्प स्पष्ट रूप से अंकित करें।

यूपी में 200 सीटों पर कांग्रेस का दावा सपा से बढ़ी गठबंधन की सरगर्मी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की ओर से लगाए गए होर्डिंग ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। इन होर्डिंग पर '200 सीट हक है हमारा, यूपी को है राहुल गांधी पर भरोसा' का नारा लिखा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 200 सीटों तक अपनी दावेदारी का राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। पार्टी के इस रुख के बीच प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को 175 से 200 विधानसभा सीटों की शुरुआती सूची सौंपी गई है। कांग्रेस का मानना है कि इन सीटों पर उसका संगठन और चुनाव लड़ने की संभावनाएं अपेक्षाकृत मजबूत हैं। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी की ओर से सीटों के बंटवारे में जीतने की क्षमता और जमीनी समीकरणों को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। ऐसे में गठबंधन की संभावित रणनीति और सीटों के तालमेल को लेकर दोनों दलों के रुख पर राजनीतिक हलकों की नजर है।

लखनऊ के कई स्थानों पर लगाए गए होर्डिंग में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की तस्वीरें भी शामिल हैं। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद इमरान मसूद और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना की तस्वीरें दिखाई गई हैं। होर्डिंग के जरिए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच चुनावी दावेदारी का संदेश देने के साथ यह संकेत भी दिया है कि वह आगामी चुनाव में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि, होर्डिंग पर लिखे नारे को सीटों के बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं माना जा सकता। गठबंधन में कितनी सीटें किस दल को मिलेंगी, यह दोनों पार्टियों के बीच होने वाली बातचीत और अंतिम समझौते पर निर्भर करेगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के अनुसार, पार्टी ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को 175 से 200 सीटों की शुरुआती सूची सौंपी है। इस सूची को कांग्रेस की ओर से उन विधानसभा क्षेत्रों की दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है, जहां पार्टी अपने संगठन, स्थानीय नेताओं और चुनावी संभावनाओं के आधार पर मजबूत स्थिति मानती है। सीटों की सूची सौंपने का उद्देश्य गठबंधन वार्ता में कांग्रेस की प्राथमिकताओं को सामने रखना है। हालांकि, शुरुआती सूची में शामिल सीटों की संख्या और अंतिम रूप से कांग्रेस को मिलने वाली सीटों के बीच अंतर हो सकता है। गठबंधन की बातचीत में क्षेत्रीय समीकरण, पिछले चुनावों के परिणाम, स्थानीय उम्मीदवारों की स्थिति और दोनों दलों के संगठनात्मक प्रभाव जैसे पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने भी सीटों के बंटवारे को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। सपा नेताओं का कहना है कि गठबंधन में सीटों का आवंटन जीतने की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए।

भारतीय रेल की वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का लाभ अब पीआरएस काउंटरों पर आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी मिलेगा,27 अक्टूबर, 2026 से सुविधा लागू; डिजिटल भुगतान और मोबाइल नंबर अनिवार्य

भारतीय रेल अपनी मौजूदा वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का विस्तार करते हुए 27 अक्टूबर, 2026 से अपने पूरे नेटवर्क में यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों पर आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी यह सुविधा प्रदान करेगी। आईआरसीटीसी के माध्यम से ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध यह योजना अब रेलवे आरक्षण काउंटरों से आरक्षित टिकट खरीदने वाले पात्र यात्रियों के लिए भी उपलब्ध होगी। पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (PCCM-WR) श्री तरुण जैन के मार्गदर्शन में पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों में यात्रियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बीमा सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक होगी। यह सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों को प्रदान की जाएगी जो बीमा का विकल्प चुनेंगे, मोबाइल नंबर देंगे और डिजिटल माध्यम से भुगतान करेंगे। लागू बीमा प्रीमियम टिकट किराये के साथ लिया जाएगा तथा किराये और प्रीमियम, दोनों का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से करना होगा। लागू नियमों एवं शर्तों के अनुसार, प्रीमियम सभी करों सहित प्रति यात्री 45 पैसे है। यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिनके टिकट की स्थिति बुकिंग के समय कन्फर्म, आरएसी या आंशिक रूप से कन्फर्म हो। बीमा का विकल्प चुने जाने पर यह एक ही पीएनआर के अंतर्गत बुक किए गए सभी पात्र यात्रियों पर लागू होगा। पाँच वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों की बुकिंग बिना बर्थ/सीट के की गई हो, वे बीमा के अंतर्गत कवर नहीं होंगे, जबकि पाँच से ग्यारह वर्ष की आयु के बच्चे बर्थ के साथ या बिना बर्थ के भी पात्र होंगे।

पॉलिसी के अंतर्गत आने वाली रेल दुर्घटना या अप्रिय घटना की स्थिति में इस योजना के तहत मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता के लिए 10 लाख, स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए 7.50 लाख तक तथा चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने के खर्च के लिए 2 लाख तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अधीन पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए 10,000 का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

यात्रियों को यात्रा बीमा संबंधी अपना विकल्प अंकित करने की सुविधा देने के लिए आरक्षण मांग प्रपत्र में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रपत्र पश्चिम रेलवे के सभी पीआरएस केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इन केंद्रों पर यात्रियों को इस सुविधा तथा इसके लिए डिजिटल भुगतान और मोबाइल नंबर की आवश्यकता के बारे में जानकारी देने हेतु उद्घोषणाएं भी की जाएंगी। आरक्षण कर्मचारी यात्रियों को बीमा के विकल्प और निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन देंगे।

बीमा पॉलिसी का विवरण यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यात्रियों को बुकिंग के बाद उपलब्ध कराए गए लिंक का उपयोग करके बीमा कंपनी की वेबसाइट पर नामांकन संबंधी विवरण भरना चाहिए। मृत्यु संबंधी दावों का निपटान घोषित नामित व्यक्ति के पक्ष में किया जाएगा अथवा नामित व्यक्ति का विवरण दर्ज न होने पर विधिक वारिस प्रमाणपत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर विधिक वारिसों के पक्ष में किया जाएगा। योजना के मौजूदा नियम एवं शर्तें पीआरएस काउंटरों से की गई बुकिंग पर भी लागू होंगी। पॉलिसी जारी करने और दावों के निपटान की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी।

इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक यात्रियों से अनुरोध है कि वे संशोधित आरक्षण मांग प्रपत्र में अपना विकल्प स्पष्ट रूप से अंकित करें।

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल ने पेयजल गुणवत्ता परीक्षण में हासिल किया 100% अनुपालन

पश्चिम रेलवे यात्रियों और रेल कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता देती है। अपने नियमित पेयजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल ने 17 से 23 अक्टूबर, 2026 के दौरान पेयजल गुणवत्ता के कुल 315 परीक्षण किए, जिनके सभी परिणाम संतोषजनक पाए गए।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस निगरानी के अंतर्गत 263 अवशिष्ट क्लोरीन परीक्षण तथा 52 जीवाणु संबंधी परीक्षण किए गए। सभी परीक्षणों के परिणाम संतोषजनक पाए गए और दोनों परीक्षण मानकों में 100% अनुपालन दर्ज किया गया।

यह निगरानी पेयजल गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने में चिकित्सा विभाग तथा संबंधित रेल कर्मचारियों के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। नियमित परीक्षण और प्रभावी पर्यवेक्षण, यात्रियों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए पश्चिम रेलवे के प्रयासों का अभिन्न हिस्सा हैं। इन सतत निगरानी गतिविधियों के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर पेयजल कूलरों तथा नलों के पानी में अवशिष्ट क्लोरीन और कुल घुलित ठोस पदार्थ (टीडीएस) की जाँच भी की जा रही है।

पश्चिम रेलवे अपने स्टेशनों और रेलवे प्रतिष्ठानों में पेयजल गुणवत्ता की नियमित निगरानी तथा सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिल्ली-यूपी से हरियाणा तक बदला मौसम, बारिश और ओलों से बढ़ी ठंड की आहट

नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि दर्ज किए जाने के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी मौसम की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है, जहां तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के बीच पूर्वी और दक्षिणी भारत के मौसम पर भी नजर रखी जा रही है। मौसम में आए इस बदलाव से एक ओर जहां गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं तेज हवाओं, ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण जनजीवन, यातायात और कृषि गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका भी बनी हुई है।

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार रात मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि देर रात कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी खबर सामने आई। मौसम के इस बदलाव से तापमान में राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश के बाद वातावरण में मौजूद धूल और कुछ प्रदूषक कणों के कम होने से वायु गुणवत्ता में अस्थायी सुधार हो सकता है, हालांकि इसका वास्तविक असर प्रदूषण के स्तर, हवा की दिशा और अगले कुछ घंटों की मौसम परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। दिल्ली में दिन के दौरान बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। अनुमान के अनुसार, अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम में आए बदलाव के बीच लोगों को तेज हवा और अचानक होने वाली बारिश को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश में भी मौसम के बदलते मिजाज का असर कई जिलों में दिखाई दे सकता है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, आजमगढ़, पीलीभीत, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, सोनभद्र, चंदौली, आगरा, मथुरा और मिर्जापुर सहित कई क्षेत्रों में मध्यम बारिश और आंधी की आशंका जताई गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम में अचानक बदलाव के कारण कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाने, गरज-चमक होने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की स्थिति बन सकती है। स्थानीय स्तर पर मौसम का प्रभाव अलग-अलग हो सकता है, इसलिए लोगों को अपने जिले के ताजा मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और पश्चिमी हिस्सों में मौसम की गतिविधियां खास तौर पर लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर सकती हैं। वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर और आसपास के जिलों में बारिश होने पर सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है। वहीं, तेज हवा के दौरान खुले स्थानों, कमजोर निर्माणों और बिजली के तारों के आसपास सावधानी बरतना जरूरी होगा। किसानों के लिए भी मौसम का यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि बारिश और तेज हवा का असर खेतों में खड़ी फसलों, कटाई के लिए तैयार उपज और कृषि कार्यों पर पड़ सकता है। हालांकि, किसी क्षेत्र में फसल को कितना नुकसान होगा, यह बारिश की मात्रा, हवा की गति और स्थानीय फसल परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसलिए किसानों को स्थानीय कृषि और मौसम विभाग की सलाह के अनुसार ही आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

हरियाणा और पंजाब में भी मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में बारिश और आंधी के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। तेज हवा के साथ बारिश होने पर सड़क यातायात प्रभावित होने और खुले स्थानों पर रखी वस्तुओं को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जालौर, सिरोही, बारां और पाली सहित कई क्षेत्रों में बारिश और आंधी की संभावना है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की परिस्थितियां अलग रह सकती हैं। कहीं हल्की बारिश हो सकती है, तो कहीं गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किए जाने की जानकारी दी गई है। ऐसे में लोगों को मौसम संबंधी स्थानीय सूचनाओं पर नजर रखने की जरूरत है। पूर्वी भारत में झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी बारिश और आंधी की आशंका जताई गई है। झारखंड के रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद समेत कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी का उल्लेख किया गया है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के कारण मौसम की गतिविधियों में तेजी आने का अनुमान है। इस तरह की मौसमी प्रणालियां समुद्र से नमी लेकर आसपास के क्षेत्रों में बादलों और वर्षा की गतिविधियों को बढ़ा सकती हैं। हालांकि, कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदलेगा या नहीं और उसका मार्ग क्या होगा, इसकी पुष्टि मौसम विभाग के ताजा आधिकारिक बुलेटिन से ही की जानी चाहिए। संभावित चक्रवाती प्रणाली को लेकर तटीय इलाकों में मौसम की निगरानी महत्वपूर्ण बनी हुई है। दक्षिण भारत में बारिश का असर उत्तर भारत की तुलना में अधिक रहने का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। केरल में भी कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी आंतरिक इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बादल बरस सकते हैं। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। तेलंगाना में भी आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रही मौसमी प्रणाली के आगे बढ़ने के साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का खतरा बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, यह प्रणाली 28 अक्टूबर के आसपास आंध्र प्रदेश और यानम के तट के निकट पहुंच सकती है। दक्षिण भारत में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और मछुआरों के लिए मौसम संबंधी निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण होगा। समुद्र में तेज हवाएं और खराब मौसम होने पर मछली पकड़ने की गतिविधियां जोखिम भरी हो सकती हैं। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी जमा होने और यातायात प्रभावित होने की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि, बारिश की तीव्रता और उसका वास्तविक प्रभाव अलग-अलग जिलों में अलग हो सकता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा चेतावनियों पर ध्यान दें।

पहाड़ी राज्यों में भी मौसम में बदलाव के संकेत हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश की आशंका है। जम्मू-कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदलता है, इसलिए ऊंचाई वाले इलाकों में जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सड़क की स्थिति, भूस्खलन की आशंका और प्रशासन की सलाह को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनानी चाहिए।

मौसम के इस बदलाव का असर खेती-किसानी पर भी पड़ सकता है। बारिश जहां कुछ क्षेत्रों में फसलों के लिए लाभकारी हो सकती है, वहीं तेज हवा, ओलावृष्टि और अत्यधिक बारिश से खेतों में खड़ी फसलों तथा कटाई के बाद खुले में रखी उपज को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की स्थानीय चेतावनियों के अनुसार फसल और कृषि उपकरणों की सुरक्षा के उपाय करें। बिजली चमकने और गरज-चमक के दौरान खुले खेतों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना चाहिए।

देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। 25 अक्टूबर के लिए जारी पूर्वानुमान और 26 अक्टूबर के नवीनतम पूर्वानुमान में अंतर है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश में व्यापक बारिश के बजाय सप्ताह के बाद के दिनों में पूर्वी हिस्सों में गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। दूसरी ओर, बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रही प्रणाली के कारण दक्षिण और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। फिलहाल, देश के कई हिस्सों में मौसम की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद उत्तर भारत के लोगों को मौसम में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जबकि दक्षिण और पूर्वी भारत में विकसित हो रही मौसमी प्रणाली आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ा सकती है। लोगों को सलाह है कि वे पुराने पूर्वानुमानों के बजाय अपने जिले के लिए जारी नवीनतम मौसम बुलेटिन को प्राथमिकता दें और तेज हवा, बिजली गिरने, भारी बारिश या बर्फबारी की चेतावनी मिलने पर आवश्यक सावधानी बरतें।

एशियन पैरा गेम्स 2026 में गुजरात के खिलाड़ियों का दबदबा, विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीते 8 मेडल

साबरकाँठा की अंजनाबेन बुंबडिया ने पैरा एथलेटिक्स की 400 मीटर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता

गांधीनगर : जापान के आइची प्रीफेक्चर और नागोया शहर में आयोजित पाँचवीं एशियन पैरा गेम्स में गुजरात के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करके राज्य और देश का गौरव बढ़ाया है। गुजरात के खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में एक गोल्ड, दो सिल्वर और पाँच ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल आठ मेडल जीते हैं।

साबरकाँठा की अंजनाबेन रोहित बुंबडिया ने पैरा एथलेटिक्स की महिला 400 मीटर टी47 प्रतियोगिता 59.97 सेकंड में पूरी करके गोल्ड मेडल जीता। उनकी इस उपलब्धि ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुजरात का गौरव बढ़ाया है।

साबरकाँठा की ही तेजलबेन अमरजी डामोर ने पैरा एथलेटिक्स में दो मेडल जीतकर विशेष उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने महिला 400 मीटर टी12 प्रतियोगिता 57.60 सेकंड में पूरी करके सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इसके अलावा; महिला 200 मीटर टी12 प्रतियोगिता 25.23 सेकंड में पूरी करके ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है।

गांधीनगर की निमिषा सीएस ने पैरा एथलेटिक्स की लॉन्ग जंप टी47 प्रतियोगिता में 5.37 मीटर की दूरी तय करके सिल्वर मेडल जीता है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा निमिषाबेन को एशियन गेम्स 2023 में भाग लेने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी। निमिषाबेन को हांगझोऊ, चीन में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीतने के लिए 30 लाख रुपए की सहायता दी गई थी।

पैरा टेबल टेनिस की महिला सिंगल्स क्लास 4-5 प्रतियोगिता में मेहसाणा की भाविनाबेन हसमुखभाई पटेल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भाविनाबेन पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। राज्य सरकार द्वारा उन्हें एशियन गेम्स 2023 में भाग लेने के लिए 5 लाख रुपए और पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी। इसके अलावा; हांगझोऊ, चीन में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में मेडल जीतने के लिए राज्य सरकार द्वारा भाविनाबेन को 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी।

अहमदाबाद की सोनलबेन मनुभाई पटेल ने पैरा टेबल टेनिस की महिला सिंगल्स क्लास 3 प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्हें एशियन गेम्स 2023 और पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने के लिए क्रमशः 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की सहायता दी गई थी।

भावनगर के राकेश धनजीभाई भट्ट ने पैरा एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके दो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उन्होंने पुरुषों की 100 मीटर टी37 प्रतियोगिता 11.50 सेकंड में और 200 मीटर टी37 प्रतियोगिता 23.64 सेकंड में पूरी करके दोनों प्रतियोगिताओं में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। उन्हें एशियन गेम्स 2023 में भाग लेने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में खेलकूद तथा खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। एशियन पैरा गेम्स में गुजरात के खिलाड़ियों की सफलता उनकी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ मनोबल का प्रतीक है। उनकी उपलब्धियाँ अन्य दिव्यांग खिलाड़ियों को खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ने, अपनी क्षमता सिद्ध करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में के.एन. विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ

विभिन्न विद्याशाखाओं के 9 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदकों से कुल 22 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया

गांधीनगर : डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित के.एन. विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विद्यार्थियों को आज जो डिग्री मिल रही है, वह केवल उनके करियर निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी एक नई दिशा है। युवाओं को केवल अच्छी नौकरी या व्यवसाय तक सीमित न रहते हुए ज्ञान के साथ विनम्रता, सफलता के साथ संवेदना और शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी निभानी है। शिक्षा चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज के प्रति समर्पण का एक सशक्त माध्यम है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि "विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रश्न पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं, लेकिन जीवन की परीक्षा में सब कुछ 'आउट ऑफ सिलेबस' ही होता है।" विश्वविद्यालय में प्रगति अंकों या मार्क्स से तय होती है, लेकिन अब जीवन की अगली मंजिल निरंतर परिश्रम के पसीने से तय होगी।

प्रधानमंत्री की 25 वर्षों की निष्ठापूर्ण जनसेवा की सराहना करते हुए उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना लगातार राष्ट्रहित और जनसेवा के लिए कार्य किया है। विश्व में ऐसा उदाहरण शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री के जीवन से प्रेरणा लेकर युवाओं को सीखना चाहिए कि "मेहनत करने से थकान नहीं होती, बल्कि मेहनत करने की खुशी का अनुभव होता है।"

वर्तमान स्टार्टअप युग का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आज डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं में से कई अपने स्टार्टअप या बिजनेस प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप, साइंस और स्किल के माध्यम से देश के युवाओं को सामर्थ्यवान बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं।

राज्य में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात में शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास को विकास के बुनियादी स्तंभों के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री कार्यकाल से ही उच्च शिक्षा को दिए गए महत्व के परिणामस्वरूप आज के.एन. विश्वविद्यालय सहित निजी विश्वविद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय शिक्षा मिल रही है। आज राज्य में लगभग 110 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा, मातृभाषा और आधुनिक विज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। आज एआई, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों के द्वार खुले हैं, जिसके कारण देश का युवा 'जॉब सीकर' से 'जॉब गिवर' बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवा शक्ति के कंधों पर है। उन्होंने शुभमकानाएँ देते हुए कहा कि डिग्री के साथ ईमानदारी और ज्ञान के साथ संवेदना जोड़कर 'विकसित भारत' के लिए 'विकसित गुजरात' बनाने के लिए सभी युवा तैयार हों।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित महानुभावों के करकमलों से विभिन्न विद्याशाखाओं के 9 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदकों से कुल 22 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा; 94 विद्यार्थियों को विभिन्न शाखाओं की डिग्रियाँ प्रदान की गईं।

इस अवसर पर के.एन. विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री बीपिनभाई पटेल, उपाध्यक्ष श्री ध्रुवभाई पटेल, उप कुलपति प्रो. वेदव्यास त्रिवेदी, डायरेक्टर जनरल डॉ. पायल बेन सिद्धपुरा, रजिस्ट्रार श्री आलोक कुमार सिंह, आमंत्रित महानुभाव प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे।

सूरत के कोसमाडा में 125 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 'इस्कॉन वराछा मंदिर' का भव्य शिलान्यास एवं सम्मान समारोह मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में आयोजित हुआ

श्रीमद्भगवद्गीता के 18 अध्याय तथा उत्कृष्ट जीवन-दर्शन मानव जीवन को नई राह दिखाते हैं : मुख्यमंत्री

गांधीनगर : सूरत के कोसमाडा में 125 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाले भव्य 'इस्कॉन वराछा मंदिर' का शिलान्यास एवं दाताओं का सत्कार समारोह मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में आयोजित हुआ।

मुख्यमंत्री ने सूरत में निर्मित होने वाले आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र समान इस्कॉन मंदिर की शिलाओं का पूजन किया तथा नरसिंह यज्ञ में आहुति दी।

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुलभाई पानशेरिया, राज्यसभा सांसद श्री गोविंदभाई धोळकिया की विशेष उपस्थिति में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के विजन का अनुसरण करते हुए विकास के साथ हमारी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का जतन सभी को करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश की आस्था के अद्वितीय केन्द्र समान राम मंदिर के निर्माण से लेकर हमारी धार्मिक विरासत को जीवंत बनाए रखने का कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है।

उन्होंने जोड़ा कि भगवत कार्य में योगदान देने तथा उसमें निमित्त बनने का अवसर मिलना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और ऐसे आयोजन समाज में दिव्यता एवं सद्भावना प्रेरित करते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे रोजमर्रा के व्यावहारिक जीवन की उलझनों और चुनौतियों के बीच श्रीमद्भगवद्गीता के 18 अध्याय हमें जीवन जीने की सच्ची राह दिखाते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रथम अध्याय के 'अर्जुन विषाद योग' से लेकर अंतिम अध्याय 'मोक्ष संन्यास योग' तक के सभी अध्याय उलझन से समझ की ओर, निराशा से आत्मविश्वास की ओर और निष्क्रियता से कर्तव्य की ओर ले जाने की प्रेरणा देते हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 'सांख्य योग' आत्मज्ञान, स्थिर बुद्धि और कर्तव्य का महत्त्व समझाता है। 'कर्मयोग' निष्काम कर्म को ही सच्ची साधना बताता है और 'ज्ञान कर्म संन्यास योग' ज्ञान से कर्म को पवित्र बनाना सीखाता है।

श्री पटेल ने कहा कि यदि गीता के इन शाश्वत मूल्यों को हम अपने जीवन में उतारें, तो परिवार मजबूत बनता है, समाज में सद्भावना बढ़ती है और राष्ट्र के विकास को मजबूत नैतिक आधार प्राप्त होता है।

उन्होंने कहा कि इस्कॉन वराछा मंदिर के शिलान्यास के इस शुभ आरंभ से आध्यात्मिकता एवं सामाजिक दायित्व का समन्वय होगा। मुख्यमंत्री ने सभी का आह्वान किया कि वे भक्ति को केवल पूजा-पाठ तक सीमित न रखते हुए उसे मानव सेवा से जोड़ें तथा युवाशक्ति को नशे से दूर रखकर राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर मोड़ें।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह संस्था भविष्य में आध्यात्मिक ज्ञान, युवा सशक्तीकरण, सांस्कृतिक जागरूकता और मानव सेवा का सर्वोत्तम केन्द्र बनेगी।

कार्यक्रम के प्रारंभ में इस्कॉन वराछा के अध्यक्ष श्री मूर्तिमानदासजी ने स्वागत संबोधन में कहा कि पूज्य श्रील प्रभुपादजी की दिव्य प्रेरणा से निर्मित होने वाला यह मंदिर आध्यात्मिकता, कृष्ण भक्ति और आस्था का दिव्य केन्द्र बनेगा। उन्होंने मंदिर निर्माण की रूपरेखा भी दी।

इस अवसर पर इस्कॉन मंदिर के निर्माण में उदारतापूर्वक सहयोग देने वाले सामाजिक अग्रणियों तथा राजस्वी दानदाताओं का मुख्यमंत्री के करकमलों से विशेष सम्मान किया गया। इसके अतिरिक्त; समग्र एशिया महाद्वीप में आयोजित श्रीमद्भगवद्गीता की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले मेधावी विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री के करकमलों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष श्री पूर्णेशभाई मोदी, विधायक श्री प्रवीणभाई घोघारी, महापौर श्रीमती मायाबेन मावाणी, इस्कॉन वराछा के अध्यक्ष श्री मूर्तिमानदास, गुजरात जोन इस्कॉन के क्षेत्रीय सचिव सहायक श्री हर्ष गोविंददास, गुजरात जोन-बी इस्कॉन के क्षेत्रीय सचिव सहायक श्री वंशीधारीदास, सामाजिक अग्रणी और राजस्वी दानदाता श्री मुकेशभाई पटेल, श्री जयंतीभाई बाबरिया, श्री विक्रमभाई सोनी, श्री वल्लभभाई सवाणी, श्री लवजीभाई डालिया, श्री ईश्वरभाई धोळकिया, श्री राकेशभाई दुधात सहित धर्मप्रेमी भक्त और श्रेष्ठी व्यक्ति उपस्थित रहे।

'राष्ट्रीय एकता दिवस - 2026' : गांधीनगर सचिवालय से 'नेशनल मोटरसाइकिल रैली' का प्रस्थान

गांधीनगर : अखंड भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर आगामी 31 अक्टूबर को एकतानगर में आयोजित होने वाली 'राष्ट्रीय एकता दिवस परेड' के उपलक्ष्य में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 'फाइट अगेंस्ट ड्रग्स' थीम अंतर्गत आयोजित भव्य 'नेशनल मोटरसाइकिल रैली' को रविवार को गांधीनगर स्थित सचिवालय परिसर से राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रस्थान कराया। सुरक्षा बलों के प्रचंड उत्साह के बीच मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रैली को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी–एकतानगर (केवडिया) की ओर रवाना कराया।

इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने रैली के बारे में जानकारी देते हुए बताया, "इस मोटरसाइकिल रैली में देश के विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की टीमें सहभागी हुई हैं। प्रत्येक राज्य से 5-5 बाइकर्स इस रैली में जुड़े हैं; जिनमें लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों तथा सीएपीएफ के जवान शामिल हैं। इस रैली में देश के विभिन्न राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों तथा सीएपीएफ की कुल 45 टीमें और 550 से अधिक जवान/अधिकारी 4 अलग-अलग जोन के माध्यम से 275 से अधिक बाइकों के साथ भाग ले रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "आज गांधीनगर से फ्लैग ऑफ होने के बाद ये टीमें आगे बढ़कर केवडिया पहुँचेंगी। रैली के समग्र मार्ग के दौरान अलग-अलग स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रमों तथा शपथ ग्रहण गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा सके। सभी बाइकर्स केवडिया पहुँचेंगे और 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में गौरवपूर्वक भाग लेंगे।"

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 21 अक्टूबर को नई दिल्ली से उत्तर क्षेत्र की इस रैली को फ्लैग ऑफ किया गया था, जो हरियाणा तथा राजस्थान से होकर गांधीनगर आ पहुँची थी। गांधीनगर से प्रस्थान करने के बाद यह रैली आणंद तथा वडोदरा होकर निर्धारित गंतव्य एकतानगर पहुँचेगी।

"से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ" (नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें) के मंत्र के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उच्च अधिकारी तथा बड़ी संख्या में जवान उपस्थित रहे।